समक्ष एम.एम पूँछी, माननीय न्यायमूर्ति।

जिले सिंह और अन्य – *अपीलकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य – प्रतिवादी

1982 की सिविल रिट याचिका संख्या 2625

11 मई, 1984

भारत का संविधान ***1950***-अनुच्छेद ***226***-भूमि अधिग्रहण अधिनियम (***1894*** का ***1)***- धारा ***4, 6*** और ***17***-धारा ***4*** और ***6*** के तहत जारी की गई अधिसूचनाएं जिसमें अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का गलत विवरण दिया गया है। अधिग्रहण की कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया और पुरस्कार की घोषणा की गई- भूमि मालिक मुआवजा दिया गया - ऐसे कुछ मालिकों ने बाद में अधिसूचनाओं को रद्द करने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की - उच्च न्यायालय को क्या ऐसे चरण में अनुच्छेद ***226*** के तहत हस्तक्षेप करना चाहिए - राज्य द्वारा लागू धारा ***17*** के तहत तत्काल प्रावधान - ऐसी कार्रवाई - क्या ऐसे में चुनौती दी जा सकती है याचिका।

अभिनिर्णित, यह माना गया कि जहां पुरस्कार तैयार करने की दिशा में कठिन प्रक्रिया शुरू की गई थी और विशेष रूप से, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 9 में, इच्छुक व्यक्तियों से दावा याचिकाएं आमंत्रित की गईं, न केवल मुआवजे के उनके दावों के संबंध में, बल्कि संबंध में भी। भूमि में उनके संबंधित हितों के लिए, और अधिसूचनाओं में हुई कुछ विसंगतियों के आधार पर कार्यवाही को चुनौती दी गई है, याचिकाकर्ता अपनी उपेक्षा और आचरण से संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत कार्यवाही में किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं। भारत की। यह ध्यान में रखना होगा कि इस तरह के अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए जाते हैं और समय की घड़ी को केवल इसलिए पीछे नहीं चलने दिया जा सकता

क्योंकि, प्रक्रिया के तहत, कुछ त्रुटि हुई है, जब तक कि गंभीर अन्याय का मामला न बना हो। . मौजूदा मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी कार्रवाई इंसानों द्वारा की जाती है और गलती करना इंसान का काम है। इस न्यायालय से राहत तभी मिलती है जब त्रुटि स्पष्ट हो और स्पष्ट अन्याय का मामला हो; अन्यथा नहीं। अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाओं के संबंध में जो कहा गया है वह अधिनियम की धारा 17 के संबंध में तर्क पर भी समान रूप से लागू होता है। याचिकाकर्ताओं ने अधिग्रहण को अंतिम रूप देने से पहले इस न्यायालय से संपर्क करने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी तरह से अधिनियम की धारा 17 की भावना के विपरीत थी।

(पैरा 2 & 3)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय विवादित अधिसूचनाओं अनुलग्नक पी-1 और पी-2 को रद्द करने की कृपा कर सकता है। आगे प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ताओं को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत प्रतिवादियों को आवश्यक नोटिस देने से छूट दी जाए क्योंकि याचिकाकर्ताओं की बेदखली कभी भी हो सकती है। यह भी प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ताओं की बेदखली पर रोक लगाई जाए और रिट याचिका की लागत भी उन्हें दी जाए।

याचिकाकर्ता के लिए वकील गुर रतन पाल सिंह।

प्रतिवादी की ओर से गोपी चंद, ए.जी. हरियाणा के वकील।

निर्णय

मदन मोहन पूँछी, माननीय न्यायमूर्ति।

(1) शुरुआत में, 39 याचिकाकर्ता थे। याचिका के लंबित रहने के दौरान उनमें से काफी संख्या में लोग मुकाबले से हट गए। शेष लोग भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित) की क्रमशः धारा 4 और 6 के तहत दो अधिसूचनाओं के खिलाफ व्यथित रहे, जिसके तहत हरियाणा राज्य ने, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए, कुछ भूमि का अधिग्रहण किया। एक अनुसंधान स्टेशन की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया प्राथमिक बिंदु यह है कि जब धारा 4 के तहत अधिसूचना 3 अप्रैल, 1981 को जारी की गई थी और उसके बाद 7 अप्रैल, 1981 को अधिनियम की धारा 6 के तहत धारा 17 के प्रावधानों को नियोजित करते हुए एक घोषणा की गई थी। अधिनियम के अनुसार, न केवल फ़ील्ड संख्याओं के विवरण में बल्कि उनके क्षेत्रों में भी बहुत सारी विसंगतियाँ थीं। यहां तक कि अधिग्रहीत की जाने वाली कुल भूमि की गणना भी गलत तरीके से की गई थी, जिसका विवरण, फैसले पर बोझ डाले बिना, याचिका के पैराग्राफ 4 से प्राप्त किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा बताई गई विसंगतियों को राज्य द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। इन्हें आकस्मिक त्रुटियों के रूप में वर्णित किया गया है जिन्हें 10 सितंबर, 1982 को आधिकारिक राजपत्र में सरकार द्वारा जारी एक शुद्धिपत्र द्वारा ठीक भी किया गया था। राज्य ने अन्यथा अपने रिटर्न के पैराग्राफ 4 में त्रुटियों को स्पष्ट कर दिया है और उनके विवरण के कारण निर्णय पर बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है।

(2) देखने वाली बात यह है कि क्या ऐसी त्रुटियों पर विवादित अधिसूचना बिल्कुल रद्द कर दी जानी चाहिए और यदि हां, तो पूरी तरह या आंशिक रूप से। इस बिंदु की सराहना करने के लिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने 25 मई, 1982 को भूमि को राज्य में निहित करने के पुरस्कार की घोषणा की थी और कुछ भूस्वामियों को, जिसकी सूची अनुलग्नक आर-एल के रूप में प्रदान की गई थी, प्राप्त भी हो गई थी। मुआवज़ा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि रिट-याचिकाकर्ताओं ने, निश्चित रूप से, जून, 1982 में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

और 21 जून, 1982 को मोशन बेंच द्वारा बेदखली पर रोक प्राप्त करते समय दो अधिसूचनाओं में विसंगतियों की ओर इशारा किया। जाहिर है, उन्होंने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। भूमि अधिग्रहण अवार्ड पारित होने के बाद. संकल्पनात्मक रूप से, यह माना जा सकता है कि पुरस्कार तैयार करने की दिशा में सभी कठिन प्रक्रियाएं शुरू की गई थीं और विशेष रूप से, अधिनियम की धारा 9 में, इच्छुक व्यक्तियों से दावा-याचिकाएं आमंत्रित की गईं, न केवल मुआवजे के उनके दावों के संबंध में बल्कि भूमि में उनके संबंधित हितों के संबंध में भी। निस्संदेह, ये धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाओं पर आधारित थे, और वास्तव में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के संबंध में किसी भी विसंगति को सभी संबंधित योजनाओं की सहायता से हल किया गया था, जिन्हें विशेष रूप से उपलब्ध होने के लिए अधिसूचित किया गया था। कार्यालय उपमण्डल अधिकारी (ना.), कैथल, जिला कुरूक्षेत्र। जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है. याचिकाकर्ताओं के लिए निर्णय पारित होने के लगभग एक महीने बाद अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाओं को चुनौती देने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, केवल सुझाए गए, यद्यपि स्वीकार किए गए, विसंगतियों पर। इस प्रकार मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता, अपनी उपेक्षा और आचरण के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इन कार्यवाही में किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं। ऐसा एक भी शब्द नहीं सुझाया गया है कि याचिकाकर्ताओं की कोई भी ज़मीन मुआवज़ा दिए बिना ले ली गई हो। यह ध्यान में रखना होगा कि इस तरह के अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए जाते हैं और समय की घड़ी को केवल इसलिए वापस चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि, प्रक्रिया के तहत, कुछ त्रुटि हुई है, जब तक कि गंभीर अन्याय का मामला न हो बनाया। मौजूदा मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी कार्रवाई इंसानों द्वारा की जाती है और गलती करना इंसान का काम है। इस न्यायालय से राहत तभी मिलती है जब त्रुटि स्पष्ट हो और स्पष्ट अन्याय का मामला हो; अन्यथा नहीं।

(3) अंत में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि अधिनियम की धारा 17 के तहत तत्काल प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। पिछले पैराग्राफ में अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाओं के संबंध में जो कहा गया है वह अधिनियम की धारा 17 के संबंध में तर्क पर भी समान रूप से लागू होता है। याचिकाकर्ताओं ने अधिग्रहण को अंतिम रूप देने से पहले इस न्यायालय से संपर्क करने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी तरह से अधिनियम की धारा 17 की भावना के विपरीत थी।

(4) किसी अन्य बिंदु पर आग्रह नहीं किया गया है।

(5) जाली कारणों से, यह याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सचिन कुमार सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा